Statement

Milk Production—1997-98 (Provisional)

(000 Tonnes)

	States	Milk (000MT)
1	Andhra Pradesh	4510
2	Arunachal Pradesh	44
3	Assam	775
4	Bihar	3475
5	Goa	39
6	Gujarat	4860
7	Haryana	4082
8	Himachal Pradesh	707
9	Jammu & Kashmir	938
10	Karnataka	3697
11	Kerala	2348
12	Madhya Pradesh	5378
13	Maharashtra	5193
14	Manipur	62
15	Meghalaya	59
16	Mizoram	20
17	Nagaland	46
18	Orissa	670
19	Punjab	7350
20	Rajasthan	5500
21	Sikkim	35
22	Tamil Nadu	4000
23	Tripura	47
24	Uttar Pradesh	12934
25	West Bengal	3415
	U.Ts.	
26	A&N Island	22
27	Chandigarh	43
28	D & N Haveli	4
29	Daman Diu	1
30	Delhi	266
31	Lakshadweep	1
32	Pondicherry	36.6
	All India	70557.6

नेपाल की नदियों के कारण बिहार में क्षति

2027. **श्री जनार्दन यादव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि ब्रहमपुत्र और नेपाल की अन्य नदियों में वर्षा ऋतु के दौरान बाढ़ आने के कारण उत्तरी बिहार के कई जिलों को जान-माल तथा करोड़ों रुपये की फसलों का नुकसान उठाना पड़ता है,

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में नेपाल सरकार के साथ कोई वार्ता की है, यदि नहीं, तो क्या सरकार वार्ता करने का विचार रखती है, और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल): (क) से (ग) सरकार को बरसात के मौसम में नेपाल से भारत में बहने वाली नदियों से उत्तरी बिहार में बाढ़ के द्वारा हुई क्षति की जानकारी है। बाढ़ नियंत्रण के प्रश्न पर नेपाल के साथ सभी स्तरों पर नियमित बातचीत होती है। विशेष रूप से, प्रस्तावित कोसी उच्च बांध परियोजना तथा नेपाल से बिहार राज्य में बहने वाली नदियों में बाढ़ नियंत्रण बांधों से संबंधित मामलों को द्विपक्षीय रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। बांध निर्माण समितियों जैसे सांविधिक निकाय भी हैं जो विषेष रूप से नेपाल से भारत में बहने वाली चार नदियों (लालबाकेया, कमला, बागमती एवं खाण्डों) पर बाढ़ नियंत्रण उपायों से संबंधित हैं । सरकार की ओर से प्रयास जारी रहेंगे।

कृषि का आधुनिकीकरण

2028. **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाद्यान्न उत्पादन के मामले में प्रत्येक राज्य विशेषकर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट् और मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि के आधुनिकीकरण के लिए विशेष योजनाओं का ब्यौरा क्या है,

(ख) राज्यों को सस्ते दामों में उन्नत किस्म के बीजों तथा उर्वरक की यथासमय आपूर्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं,

(ग) क्या उक्त राज्यों में उर्वरकों की खपत और उपलब्धता अन्य राज्यों की तुलना में कहीं कम हैं, और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाए किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल): (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा सभी राज्यों में कृषि के विकास के

लिए बहुत सी केन्द्रीय/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं सहित इन योजनाओं की सूची विवरण में संलग्न हैं (नीचे देखिए)।

(ख) किसानों को उचित मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता वाले बीज तथा उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए, सरकार विभिन्न योजनाओं के जरिये वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

(ग) और (घ) वर्ष 1997-98 के दौरान देश में पोषक तत्वों के संदर्भ में उर्वरकों की 87.45 कि०ग्रा० प्रति हैक्टेयर की औसत खपत (अनुमानित) की तुलना में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान में प्रति हैक्टेयर खपत क्रमश: 97.47 कि०ग्रा०, 51.63 कि०ग्रा०, 73.40 कि०ग्रा० तथा 39.53 कि०ग्रा० रही है। इन चार राज्यों से हालांकि रबी मौसम में यूरिया के अभाव की कोई सूचना नहीं मिली है, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में डी०ए०पी० की कमी की कुछ रिपोर्ट मिली हैं यद्यपि इन उर्वरकों की सप्लाई और विवरण पर कोई नियंत्रण नहीं है, भारत सरकार ने विनिर्माताओं/आयातकों को इन राज्यों में सप्लाई भेजने का अनुरोध एवं आग्रह किया है।

विवरण

कृषि तथा सहकारिता विभाग द्वारा राज्यों में कार्यान्वित प्रमुख केन्द्रीय/केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की सूची

क्र०सं०	योजना का नाम	राज्य जहां क्रियान्वयन हो रहा है
1	2	3
1.	समेकित अनाज विकास कार्यक्रम - चावल	आंध्र प्रदेश, असम, अरूणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
2.	समेकित अनाज विकास कार्यक्रम - गेहूं	हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश
3.	समेकित अनाज विकास कार्यक्रम - मोटे अनाज	गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, सिक्किम
4.	गन्ना आधारित फसल प्रणाली का सतत विकास	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
5.	गहन कपास विकास कार्यक्रम	आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश
6.	राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना	सभी राज्य
7.	तिलहन उत्पादन कार्यक्रम	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, अरूणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।
8.	वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए रा०फ०वि०	सभी राज्य
9.	उर्वरकों का समेकित तथा संतुलित उपयोग	उत्तर-पूर्वी राज्यों को छोड़कर सभी राज्य
10.	राष्ट्रीय बीज परियोजना-III	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
11.	समेकित कीट प्रबंध केन्द्रों के तहत राज्य जैव-नियंत्रण प्रयोग-शालाओं को स्थापित	सभी राज्य

1	2	3
	करने/सुदृढ़ीकरण करने हेतु राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सहायता अनुदान	
12.	छोटे किसानों में कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन	सभी राज्य
13.	नदी घाटी परियोजनाओं के आवाह-क्षेत्रों में भूमि संरक्षण	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।
14.	बाढ़ प्रवण नदियों के आवाह-क्षेत्रों में मृदा संरक्षण	बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।
15.	झूम खेती क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना	केवल पूर्वोत्तर राज्यों में
16.	कृषि में प्लास्टिक का प्रयोग	सभी राज्य
17.	समेकित काजू विकास कार्यक्रम	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल।
18.	समेकित मसाला विकास	सभी राज्य
19.	एल.डी.बी. के ऋणपत्रों में निवेश	सभी राज्य

Modernisation of Vegetable production methods

2029. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) in view of the present shortage of all kinds of vegetables, whether Government plan to modernise the methods of production of vegetables to increase the production and also to produce them with lesser cost per unit;

(b) if so, the details thereof;

(c) if not, in what way Government plan to increase the supply of vegetables and also reduce its prices; and

(d) whether Government will also plan to bring such production activities under the cover of Agro-Industries so that the organised sector can be allowed to take up such production in large scale, if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) to (c) Yes, Sir. To modernise and increase vegetable production emphasis is being given on production of F-1 hybrids of important vegetable crops, adoption of improved agrotechniques, use of drip and sprinkler system of irrigation, integrated pest management etc.

(d) The organised sector can take up production of vegetables with the improved methods within the land ceiling laws of the respective States.

NAFED's role

2030. SHRI K.M. SAIFULLAH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the role played by NAFED in controlling and supplying the prices of onions in North India, recently;

(b) whether the working of NAFED and its role were satisfactory; and

(c) the measures proposed to streamline the working of NFED to make the organisation more consumer friendly?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) As per the directions of the Department of Consumer Affairs, Government of India, NAFED produced onions from the Mandies in the States of Maharashtra, Gujarat, Karnataka, Rajasthan etc. and supplied the same to the designated agencies for distribution